MEDIA/LKO/0002

Pg-01

लखनऊ | 30 अक्टूबर 2014 गुरुवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

गन्ना रिकवरी का होगा तकनीकी ऑडिट

बीएस संवाददाता
लखनऊ, 29 अक्टूबर

उत्तर प्रदेश सरकार की योजना

- राज्य के मुख्य सचिव ने पेराई सत्र 2014-15 के लिए राज्य परामर्श मूल्य निर्धारण से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की
- गन्ना किसानों को लाभ दिलाने के लिए रिकवरी तथा उत्पादकता बढ़ाई जाए
- गन्ना किसानों एवं चीनी मिलों के हितों को देखते हुए पेराई का कार्य जल्द शुरू कराया जाए

चीनी मिलों की कमजोर गन्ना रिकवरी की शिकायत को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र के दौरान तकनीकी ऑडिट कराने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा है कि गन्ना किसानों एवं चीनी मिलों के हितों को देखते हुए पेराई का कार्य जल्द शुरू कराया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ना उत्पादकता एवं रिकवरी को और अधिक बढ़ाए जाने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई जाए ताकि किसानों एवं चीनी मिल मालिकों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों का भविष्य गन्ने पर निर्भर करता है इसलिए गन्ना किसानों एवं चीनी मिलो के हितों को ध्यान में रखते हुए गन्ना मूल्य का निर्धारण यथाशीघ्र तय किया जाए। उन्होंने कहा कि चीनी मिल मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान समय से प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य तय करते समय यह अवश्य ध्यान दिया जाएगा कि चीनी मिल मालिकों का नुकसान न होने पाए लेकिन गन्ना किसानों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों में रिकवरी पर होने वाले नुकसान का तकनीकी ऑडिट भी कराए जाने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

मुख्य सचिव पेराई सत्र 2014-15 के लिए राज्य परामर्श मूल्य निर्धारण से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है लेकिनचीनी मिलों के संचालन में आने वाली बाधाओं को भी प्राथमिकता से दूर कराया जाए। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की बेहतर किस्म के गन्ने का वाजिब मूल्य अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को चीनी मिल मालिकों के माध्यम से प्राप्त होने वाली सब्सिडी उनकी मांग पर सीधे उपलब्ध कराए जाने पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को लाभ दिलाने के लिए रिकवरी तथा उत्पादकता बढ़ाई जाए।

प्रमुख सचिव, गन्ना विकास राहुल भटनागर ने कहा कि गन्ना मूल्य के निर्धारण के लिए गन्ना किसानों एवं चीनी मिल मालिकों द्वारा दिए गए आकलन पर निर्णय लेने के लिए गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि किसानों के हित के साथ-साथ चीनी मिल मालिकों का भी नुकसान न होने पाए।

बैठक में चीनी मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों, गन्ना किसान प्रतिनिधियों, खांडसारी यूनिट के प्रतिनिधियों सहित फेडरेशन एवं गन्ना वैज्ञानिकों ने भी गन्ना मूल्य निर्धारण के लिए अपनी राय व्यक्त की।

Scan